<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>06.03.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के मामले में केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं; बूनेटी चाणक्य और उनकी संबंधित संस्थाओं; डोंथिरेड्डी वासुदेव रेड्डी के रिश्तेदारों और संस्थाओं; और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की **441.63 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियां बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, भूमि पार्सल और अन्य अचल संपत्तियों के रूप में हैं।

ईडी ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव की शिकायत पर आईपीसी, 1860 की धारा 120-बी, 409 और 420 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें सरकारी खजाने को 4000 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया गया था।

पीएमएलए की जांच से पता चला है कि 2019 से पहले आंध्र प्रदेश राज्य में शराब का व्यापार एक पारदर्शी और स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित होता था, जिससे खरीद, आपूर्ति और बिक्री की पूरी डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित होती थी और एक सत्यापन योग्य इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट रिकॉर्ड बनता था। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद, नवगठित राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) द्वारा संचालित सरकारी खुदरा दुकानों (जीआरओ) के माध्यम से खुदरा शराब की दुकानों पर एकाधिकार स्थापित कर दिया। आपराधिक साजिश के तहत, स्वचालित प्रणाली को जानबूझकर निष्क्रिय कर दिया गया और उसकी जगह मैनुअल प्रणाली लागू कर दी गई, जिससे आपूर्ति आदेश (ओएफएस) जारी करने में एपीएसबीसीएल के अधिकारियों को असीमित विवेकाधिकार प्राप्त हो गया।

स्थापित शराब ब्रांडों के साथ भेदभाव करने के लिए मैनुअल OFS प्रणाली का दुरुपयोग किया गया, जिसके तहत उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया गया या बाजार से हटा दिया गया। साथ ही, रिश्वत लेकर चुनिंदा "पसंदीदा" ब्रांडों को तरजीही और अनियमित आवंटन दिए गए। इस योजना के तहत, सिंडिकेट ने कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई मूल कीमतों के साथ "मिलते-जुलते नामों वाले ब्रांड" (SSB) को बाजार में लाने को बढ़ावा दिया। इस मूल्य हेरफेर से ऐसे ब्रांडों का निर्माण करने वाली शराब बनाने वाली भट्टियों को अतिरिक्त लाभ कमाने में मदद मिली, जिसका उपयोग कार्टेल की अवैध वित्तीय मांगों को पूरा करने के लिए किया गया।

पीएमएलए की जांच में यह भी पता चला कि ओएफएस (ऑफिस ऑफ स्टॉक) की मंजूरी प्राप्त करने की शर्त के रूप में डिस्टिलरियों को प्रति केस मूल मूल्य के 15% से 20% तक अवैध रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया था। अनुपालन करने से इनकार करने वाले निर्माताओं को वैध भुगतानों को रोकने और आपूर्ति आदेशों को रद्द करने सहित दमनकारी उपायों का सामना करना पड़ा। रिश्वत की मांग और वसूली से संबंधित संचार एन्क्रिप्टेड वीओआईपी कॉल और सिग्नल जैसे एप्लिकेशन के माध्यम से किया गया था, ताकि बूनेटी चाणक्य (उर्फ प्रकाश), मुप्पिडी अविनाश उर्फ सुमीत और मोहम्मद सैफ सहित प्रमुख संचालकों की पहचान और भूमिकाओं को छिपाया जा सके।

ईडी की जांच में पता चला कि श्री केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने शराब सिंडिकेट के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश राज्य में शराब की खरीद और वितरण प्रणाली में करोड़ों रुपये का घोटाला किया। इस घोटाले में मुख्य रूप से एपीएसबीसीएल की खरीद प्रक्रिया पर नियंत्रण और

हेरफेर शामिल था, जिसके कारण राज्य के खजाने को लगभग 3,500 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ। इस घोटाले से प्राप्त धन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सिंडिकेट के सदस्यों में बांटकर व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। श्री केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने श्री बूनेती चाणक्य, श्री मुप्पिडी अविनाश रेड्डी, श्री तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी, श्री पैला दिलीप, श्री सैफ अहमद और अन्य लोगों के साथ मिलकर लगभग 3500 करोड़ रुपये की रिश्वत ली।

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने कई शराब बनाने की भट्टियों पर नियंत्रण स्थापित किया और/या हासिल किया, जिनका उपयोग अपराध की आय अर्जित करने के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीई) के रूप में किया गया था। मेसर्स अदन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लीला डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स यू.वी. डिस्टिलरीज जैसी संस्थाएं इस गिरोह के प्रभावी नियंत्रण में संचालित होती थीं और राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव का दुरुपयोग करके उन्हें अत्यधिक मात्रा में व्यवसाय दिया जाता था ताकि इन भट्टियों के संचालन से प्राप्त वित्तीय लाभ के रूप में अपराध की आय अर्जित की जा सके।

अवैध राजस्व सृजन का एक अन्य ज्ञात स्रोत एपीएसबीसीएल द्वारा जारी निविदाओं के माध्यम से दिए गए शराब परिवहन अनुबंधों में हेराफेरी था। जांच में पता चला कि मेसर्स सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को एक केंद्रीकृत परिवहन निविदा दी गई थी, जिसकी दरें पहले के डिपो-वार परिवहन लागतों से काफी अधिक थीं। हालांकि अनुबंध एसएससीएसपीएल के नाम पर दिया गया था, लेकिन परिचालन नियंत्रण शराब सिंडिकेट के सदस्यों, मुख्य रूप से टी. ईश्वर किरण कुमार रेड्डी, सैफ अहमद और अन्य द्वारा किया जाता था। यह स्थापित किया गया है कि अनुबंध से प्राप्त राशि का एक बड़ा हिस्सा टीईकेकेआर, अर्रोयो और ईज़ीलोड जैसी संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया था, जिनका उपयोग अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने के लिए किया जाता था।

जांच से पता चला है कि कई शराब बनाने वाली कंपनियों ने कच्चे माल और पैकेजिंग सामग्री की कथित आपूर्ति के लिए विक्रेताओं और फर्जी संस्थाओं को नियुक्त किया था। इन विक्रेताओं ने उन वस्तुओं के लिए फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाकर बैंक फंड को अवैध नकदी में परिवर्तित करने में मदद की, जिनकी वास्तव में कभी आपूर्ति ही नहीं की गई थी। इसके अलावा, अपराध से प्राप्त धन को रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करके और व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह स्थापित हो गया है कि दागी धन को मेसर्स एशानवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (ईआईपीपीएल), मेसर्स ईडी एंटरटेनमेंट, मेसर्स यूनि कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टैग डेवलपर्स और अन्य संबंधित संस्थाओं के माध्यम से जमीन के टुकड़े खरीदने और आवासीय विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए भेजा गया था। जांच में यह भी पता चला है कि फर्जी और पिछली तारीखों वाले समझौतों का उपयोग करके अवैध धन को वैध व्यावसायिक प्राप्तियों के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया था।

आगे यह भी सामने आया है कि अपराध से प्राप्त धन के आपराधिक स्रोत को छिपाने और उसे वैध दिखाने के लिए, गिरोह ने ओलविक, कृपाती, नाइस्ना मल्टीवेंचर्स, अर्रोयो, ईज़ीलोड, डी-कार्ट और अन्य जैसी फर्जी और दिखावटी संस्थाओं के जटिल नेटवर्क के बैंक खातों का इस्तेमाल किया। इन संस्थाओं का उपयोग अवैध रूप से किए गए लेन-देन के जाल के माध्यम से धन को छिपाने के लिए किया गया, जिससे अवैध स्रोत और आय की प्रकृति को छिपाया जा सके और अपराध से प्राप्त धन को बेदाग दिखाया जा सके।

ईडी की जांच में पता चला कि खरीद और आपूर्ति तंत्र में हेराफेरी करके, गिरोह ने लगभग 100 करोड़ रुपये प्रति माह की अवैध आय अर्जित की, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत रूप से अनुचित लाभ हुआ और राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया है कि रिश्वत की नकद राशि हैदराबाद में कई स्थानों पर एकत्र और संग्रहीत की गई थी, जहां से गिरोह के नामित नकदी संचालकों द्वारा इसे स्थानांतरित, वितरित या निपटाया जाता था।

ईडी की जांच में अब तक 1048.45 करोड़ रुपये की रिश्वत का पता चला है, जो कई शराब कारखानों को नकद, सोने आदि के रूप में दी गई थी। साथ ही, शराब सिंडिकेट द्वारा कुछ शराब कारखानों पर नियंत्रण और संचालन के माध्यम से और शराब के परिवहन से प्राप्त वित्तीय लाभ के रूप में भी रिश्वत दी गई थी। पीएमएलए जांच में पता चला है कि अपराध से प्राप्त धन का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद और शराब सिंडिकेट के सदस्यों और उनके सहयोगियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था। अपराध से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा आरोपियों द्वारा छिपाया या नष्ट किया गया पाया गया है।

आगे की जांच जारी है।